EDITORIAL

3 Day strike

A glorious 3 day strike took place in the country from 18.2.2019 to 20.2.2019 in BSNL. The strike was a big success in all circles baring a few. The strike proved the commitment of workers to save BSNL at this crucial juncture. All Central Trade unions and pensioner associations also extended their fullest support to the 3 day strike. Why the strike was taken up by all unions/associations in BSNL? What is the necessity of it? This question was raised in all social media in the circles.

BSNL was formed on 01-10-2000, the group of Ministries (GOM) constituted under the chairmanship of Ministry of communications, Shri Ram Vilas Paswan Ji, decided that Govt will guarantee pensionery benefits to all Telecom employees after corporatization, Job security of the employees will be ensured even after their absorption in Corporate entity, Financial Viability of Bharat Sanchar Nigam Limited to be fully taken care of. These were achieved with united struggles of NFTE, FNTO & BMS in September, 2000. The strike was an historic one in the history of P&T movement. We salute our beloved father Com. O.P.G. for his strong determination.

BSNL is having 1.8 lakh employees (Executives and Non-Executives), in which 39000 employees were recruited after formation of BSNL and above 2 lakh BSNL pensioners are there. The Company was in profit of Rs. 10,000 crores till 2004-05. BSNL was in the revival path and was posting operational profits during 2014-15, 2015-16 and 2016-17. After entry of Reliance Jio in 2016, the tariff's were made "frees" to grab the subscribers in the market. All Telecom Companies are running loses, a few were closed also. There was a drastic fall down in revenue in this stiff competition, BSNL survived with the hard work of employees. But, the hidden agenda policies of Govt ruined the entity very badly.

BSNL was severely attacked by "TRAI" policies, Niti Ayog recommendations and IIM (A) report. GOM's decision on financial viability of Company is on paper since 2000. No financial support was given by the Govt in all these years to BSNL. For that only, the AUAB leaders started discussion with BSNL management/DOT authorities. No fruit full result was yielded. The AUAB leaders requested MOC(I/C) for allotment of 4G spectrum to BSNL and settle the pension contribution on actual basic on 24.2.2018. And all the dues from DOT/MTNL be reimbursed to BSNL immediately. If these issues were settled, there will be improvement in the financial status of the company.

The other burning issues are 3rd PRC/Wage revision to BSNL employees from 01-01-2017, pension revision of retired employees by de-linking with Wage Revision. There was a discontentment in DR employees, where their left out issues of 2nd PRC were not settled. Increase in pension contribution agreed by CMD BSNL in front of Hon'ble Minister also not settled till this time. For settlement of 3rd PRC/Wage revision of BSNL employees was turning in so many ways to delay it. Reducing the retirement age, VRS and CRS have come into lime light. These developments were irritated executives and non-executives in the entity, which is not good for the Company growth. On the name of financial condition of Company, the salary deductions like LIC/Bank loans/Society were not send to respective heads since 3,4 months. Who is responsible for all these developments? the management/Govt should not be a mute spectator at this juncture.

To resolve all the issues the AUAB leaders started discussions with Corporate management/DOT Authories/Hon'ble MOC (I/C) from 24.2.2018. The AUAB organized Dharnas/Rallies in the country. At one point of time on 3.12.2018, all the said authorities assured to AUAB Leaders that the issues will be settled in short time. So, the indefinite strike was deferred, which is to be begin from 3.12.2018. But, the management failed to do justice to Company as well as to employees. In this unavoidable situation the AUAB leaders called 3 day strike from 18.2.2019 to 20.2.2019. The above said conditions prevailed in these days so, the strike was warranted from 18.2.2019.

Comrade, we organized so many strikes in the past. We should not be disappointed at all. Struggle is right path to save BSNL entity and to achieve our genuine demands. Struggle is not over, we have to get ready for sacrifices to reach our goal to save BSNL. Com. O.P.G. was telling that "we break our heads but not unity".

संपादकीय

तीन दिवसीय हड़ताल

राष्ट्रीय पैमाने पर भारत संचार निगम लिमिटेड के एक लाख सतर हजार एग्जीक्यूटीव एवं नॉन एग्जीक्यूटीव कर्मचारियों ने दिनांक 18 से 20.2.2019 तक तीन दिनों कि एतिहासिक हड़ताल करके अपने आक्रोश जाहिर की उक्त हड़ताल में कर्मचारियों ने बी.एस.एन.एल की सुरक्षा के प्रति अपने प्रतिबधता को साबित किया। सभी राष्ट्रीय संगठनों एवं पेंशनरों के संगठन ने अपना पूर्ण समर्थन हड़ताल के प्रति जाहिर किया। सभी समाचार माध्यमों ने इस सफल हड़ताल के कारणों पर प्रकाश डाला हैं।

ज्ञात्वय है कि भारत संचार निगम लिमिटेड की स्थापना दिनांक 1.10.2000 को तत्कालीन सरकार के निर्णय के आलोक में किया था। उक्त अवसर पर दूरसंचार विभाग में संचालित तीन श्रमिक संघों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की तथा 6 सितंबर 2000 से तीन दिनों की पूर्ण सफल हड़ताल होने के बाद सरकार द्वारा तत्कालीन संचारमंत्री श्री राम विलास पासवान के नेतृत्व में छः केंद्रीय मंत्रियों कि एक समिति गठित की गईं। उक्त समिति ने कर्मचारी संघों के साथ वार्तालाप के उपरांत (1) नौकरी की सुरक्षा, (2) सरकारी कोष से पेंशन का भुगतान तथा (3) बनने वाले निगम कि आर्थिक जीवंतता अक्षुण बनाने रखने की सरकारी निर्णय के बाद हड़ताल समाप्त की गई यह उपलब्धता हमारे प्रिय नेता स्व. का. ओ.पी गुप्ता के नेतृत्व में हासिल की गई है।

वर्तमान में भारत संचार निगम लिमिटेड में एक लाख सत्तर हजार अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद है जिसमें उन्चालिस हजार कर्मचारी बी.एस.एन.एल द्वारा नियुक्त है इसके अतिरिक्त लगभग 2 लाख बी.एस.एन.एल पेंशनर हैं। यह कंपनी वर्ष 2004–2005 तक 10 हजार करोड़ के लाभ में चल रही थी। 40 हजार करोड़ रूपया का फिक्स डिपोजिट था। सरकार के गलत नीतियों एवं कंपनी के प्रति उदासीन रवैये के चलते बीएसएनएल में आर्थिक ह्रास शुरू हुआ। श्रमिक संघों के आह्वाल पर बीएसएनएल के कर्मचारियों/अधिकारी के अथक परिश्रम द्वारा कंपनी को उत्थान कि ओर अग्रसर किया, फलस्वरूप कंपनी 2014–2015, 2015–2016 तथा 2016–2017 में कंपनी आपरेशनल प्रोफिट के साथ अग्रसर हुई परंतु अक्टूबर 2016 में रिलायंस जियो कम्पनी को दूरसंचार क्षेत्र में प्रवेश के उपरांत समस्त दूरसंचार अपरेटरों की सेवा स्थिति चिंताजनक हो गई क्योंकि रिलायंस जियो कम्पनी ने अपने उत्पाद का मुफ्त वितरण शुरू कर दिया। सरकार मुक दर्शक बनकर रिलायंस कंपनी का समर्थन करती रही।

बी.एस.एन.एल कंपनी भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण द्वारा नीति आयोग, आई.आई.एम कि अनुसंशा तथा पूर्व में कई सलाहकारों के अनुसंशाओं कि थपेड़े खाते हुये अपने आर्थिक जिवंतत्वा को खोने लगी है।

उपयुक्त स्थितियों के मुद्देनजर बीएसएमएल अधिकारियों/कर्मचारियों एयूएबी के नेतृत्व में संघर्ष कि शुरूआत की। लगातार संघर्ष के उपरांत दिनांक 24.2.2018 को एयूएबी के नेतृत्व तथा माननीय संचार राज्य मंत्री श्री मनोज कुमार सिंहा जी एवं दूरसंचार विभाग के सर्वोच्च अधिकारियों एवं बीएसएनएल बोर्ड के उच्च पदस्थ प्रबंधकों की उपस्थिति में बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में माननीय मंत्री महोदय ने कर्मचारी/अधिकारियों संघों के पांच सूत्री मांगों पर विस्तृत चर्चा के उपरांत समस्त मांगों को 31.30.2018 के पूर्व पूरा करने का अश्वासन दिया मंत्री महोदय एवं उच्च पदस्थ अधिकारियों के अश्वासन के उपरांत एयूएबी ने अपना आंदोलनात्मक कार्यवाही लगभग नवमाह तक स्थगित रखा। लंबे अंतराल तक अपने मांगों के प्रति कुछ भी सापेक्ष निर्णय नहीं होने के कारण एयूएबी ने 14 नंवबर 18 को संचार भवन मार्च किया जिसमें पांच हजार से अधिक अधिकारी एवं कर्मचारियों ने भाग लिये और उसी दिन 3 दिसंबर 2018 से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की गई। सम्पूर्ण अधिकारियों/कर्मचारियों में व्यप्त आक्रोश के कारण होने वाले हड़ताल की अभूत तैयारी सम्पूर्ण राष्ट्र में हुई परंतु एयूएबी

नेतृत्व के साथ फिर से सरकार ने छल किया। घटनाक्रम इस प्रकार आगे बढ़ी 2 दिसंबर 2018 को एयूएबी में सम्मलित संघटनों के महामंत्री संचार भवन में बुलाये गये पूरे दिन दूरसंचार आयोग के उच्च पदस्थ अधिकारियों से वार्ता होती रही वेतन पुनः निरिक्षण समेत सारी मांगों को अग्रसर करने की बातें दोहराई गई तथा दूरसंचार सचिव द्वारा यह बताया गया कि संचार मंत्री दिल्ली से बाहर है वे तीन दिसंबर 2018 की सुबह दिल्ली पहुँचने वाले हैं। मंत्री महोदय आपसे वार्ता करना चाहते हैं अतः उनसे वार्ता होने तक आप लोग अपना हड़ताल स्थगित कर दे। एयूएबी ने तीन दिनों के लिए हड़ताल के स्थगित कर दी। दिनांक 3.12.2018 को माननीय मंत्री महोदय से एयूएबी नेतृत्व की वार्ता हुई और पूर्व के भांति सभी मांगों पर ढेड़ माह के अंदर सापेक्ष प्रतिफल देने का अश्वासन दिया। तत्संबंधी लिखित पत्र भी निर्गत किया गया। राष्ट्रीय मंत्री के स्पष्ट अश्वासन की अवहेलना उचित नहीं समझते हुये एयूएबी नेतृत्व में डेढ़ माह के लिए हड़ताल को स्थगित कर दिया दो माह बीत जाने के बाद भी किसी भी बिंदू पर कोई प्रगति नहीं होने के स्थिति में फिर से हड़ताल की नोटिस जारी की गई। तदानुसार 18 फरवरी 2019 से 20 फरवरी 2019 तक तीन दिनों वित्त दिनों कि ऐतिहासिक हड़ताल राष्ट्रीय पैमाने पर सफल हुई।

साथियों हमने लगातार संघर्ष किये हैं, कई हड़ताल भी की हैं, हमारे संघर्ष ने ही बी.एस.एन.एल को सुरक्षित रखा है इसलिए हतोतशाह होने के बजाय अपने जुझारू एकता को बनाये रखे तथा आगे के संघर्ष के लिए तैयार रहें, श्रमिकों का त्याग एवं बलिदान कभी व्यर्थ नहीं होता यह सीख हमने का. ओ.पी. गुप्ता से पाई है तथा उनका कथन कि अपना सिर फोड़ सकते हैं पर अपने चट्टानी एकता को अक्षुण बनाये रखेंगे। सफलता और कामयाबी संघर्ष से ही प्राप्त होती है।